www.deshkiupasana.com

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

DKU LIVE

सब पर नज़र, सबकी ख़बर

वर्ष – 04 | अंक – 230 | जौनपुर शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

केरल विधानसभा चुनाव के लिए तैयार, 140 सीटों के लिए 9 अप्रैल को होगा मतदान

केरल, (एजेंसी)। केरल में 9 अप्रैल को विधानसभा के 140 सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। कुल 27 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं, जिनमें 33 करोड़ पुरुष, 39 करोड़ महिलाएं और 273 ट्रांसजेंडर व्यक्ति शामिल हैं। मतदाताओं में 24 लाख से अधिक प्रवासी मतदाता भी शामिल हैं, जो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया की व्यापकता और विविधता को रेखांकित करता है। राज्य भर में 30,495 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें मतदान प्रबंधन के लिए 24 सहायक बूथ भी शामिल हैं। विशेष रूप से 352 मतदान केंद्रों का संचालन पूरी तरह से महिलाओं द्वारा किया जाएगा, जबकि 37 मतदान केंद्रों का संचालन दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा।इस बीच, सभी शीर्ष राजनीतिक नेताओं ने अपने मतदान के समय और स्थान की जानकारी मीडिया को दे दी है, जिससे उनकी संबंधित पार्टियों का प्रचार हो रहा है। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल कल गुरुवार सुबह 8रू30 बजे अलाप्पुझा में मतदान करेंगे, जबकि केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ कन्नूर में सुबह 7 बजे अपना वोट डालेंगे। विपक्ष के नेता वीडी सतीशन भी परवूर में सुबह 7 बजे मतदान करेंगे।

भारी बर्फबारी के बावजूद केदारनाथ यात्रा की तैयारियां तेज गति से जारी

उत्तराखंड, (एजेंसी)। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में लगातार हो रही भारी बर्फबारी के बावजूद केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियां पूरे जोर–शोर से चल रही हैं। प्रशासन ने मौसम की चुनौतियों के सामने घुटने नहीं टेके हैं और धाम व पैदल मार्ग पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं समय पर पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहा है। वर्तमान में केदारनाथ धाम तक खाद्य सामग्री, निर्माण सामग्री और अन्य आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति घोड़े–खच्चरों के माध्यम से लगातार की जा रही है। मोटी बर्फ की परत जमने और कठिन मौसम के बावजूद श्रमिकों और पशु चालकों की मेहनत से सामान धाम तक पहुंचाया जा रहा है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा स्वयं तैयारियों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वे विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें कर रहे हैं और मौके की स्थिति के अनुसार जरूरी दिशा–निर्देश दे रहे हैं। प्रशासन का पूरा फोकस यात्रा मार्ग को सुरक्षित बनाने, आवास व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं, सुरक्षा और अन्य मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने पर है। प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि भले ही मौसम चुनौतीपूर्ण बना हुआ है, लेकिन केदारनाथ यात्रा को सुचारु, सफल और सुरक्षित बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

आइए, हम मिलकर भारत की नारी शक्ति को सशक्त करें : प्रधानमंत्री मोदी

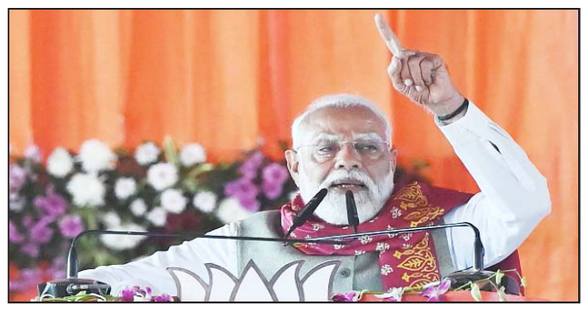

नई दिल्ली, (एजेंसी)। यह क्षण इसलिए भी विशेष है, क्योंकि यह ऐसे समय में आ रहा है जब देश का वातावरण उत्सव, नवीनता और सकारात्मकता से भरा हुआ है। आने वाले दिनों में भारत के अलग अलग हिस्सों में अनेक पर्व मनाए जाएंगे। असम के लोग रोंगाली बिहू मनाने वाले हैं, और ओडिशा में महा बिशुबा पणा संक्रांति का उत्सव मनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में पोइला बैशाख के साथ बंगाली नववर्ष की शुरुआत होगी। केरलम में विषु पूरे उत्साह के साथ मनाया जाएगा। तमिलनाडु के लोग उत्सुकता से पुथांडु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो पंजाब और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में लोगों को बैसाखी के पर्व का इंतजार है। हमारे ये पावन पर्व हर किसी में एक नई आशा का संचार करने वाले हैं। भारत के साथ–साथ दुनियाभर में इन त्योहारों को मनाने वाले सभी लोगों को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। मैं ये कामना करता हूं कि ये दिव्य और पावन अवसर हम सभी के जीवन में सुख–समृद्धि लेकर आएं। इसी दौरान 11 अप्रैल से महात्मा फुले की 200वीं जयंती के समारोह भी शुरू होंगे। 14 अप्रैल को हम भारतवासी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की जयंती मनाएंगे। ये दोनों तिथियां हमें सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा के उन मूल्यों की भी याद दिलाती हैं, जिन्होंने आधुनिक होते भारत की दिशा तय की हैं। इन्हीं प्रेरणादायी अवसरों के बीच, 16 अप्रैल को संसद की ऐतिहासिक बैठक होगी। महिला आरक्षण को लागू करने से जुड़े महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के बाद उसे पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाया गया है। इसे सिर्फ एक विधायी प्रक्रिया कहना इसके महत्व को कम करके आंकना होगा। यह भारतवर्ष की करोड़ों महिलाओं की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। हमारी नारी शक्ति देश की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया है। आज देश के हर सेक्टर में नारी शक्ति मिसाल बन रही है।

नीतीश कुमार 14 अप्रैल को देंगे सीएम पद से इस्तीफा, बिहार में नई सरकार कब लेगी आकार

पटना, (एजेंसी)। बिहार सीएम नीतीश कुमार गुरुवार को दिल्ली जा रहे हैं। शुक्रवार को वे राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। इसके साथ चर्चा तेज हो गई है कि वे मुख्यमंत्री के पद से कब इस्तीफा देंगे और राज्य में एनडीए की नई सरकार कब तक आकार लेगी। इसकी संभावित तारीख लगभग फाइनल हो गई है। नई सरकार का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी(बीजेपी) करेगी, इसकी घोषणा जदयू नेता विजय चौधरी कर चुके हैं। हालांकि, किसी चेहरे पर मुहर नहीं लगी है। कई नाम चर्चा में हैं लेकिन सामाजिक समीकरण का ताना बाना बरकरार रखने के मकसद से सबसे अधिक चर्चा सम्राट चौधरी के नाम की है।कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सांसद विधिवत बन जाने के बाद भी बिहार सीएम की कुर्सी पर बने रहेंगे। 14 अप्रैल को नीतीश कुमार सीएम पद से स्वेच्छा से इस्तीफा दे देंगे। दिल्ली से लौटकर मंत्रिमंडल की बैठक होगी। 13 अप्रैल को कैबिनेट मीटिंग की चर्चा है जिसे नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक माना जा रहा है। अगले दिन 14 अप्रैल को नीतीश कुमार राज्यपाल को त्यागपत्र सौंप देंगे।अगले दिन नई सरकार के नए मुखिया शपथ लेंगे। नई सरकार की रूपरेखा अंतिम दौर में है। कहा जा रहा है कि अगली सरकार के गठन में नीतीश कुमार की इच्छा और योजना के अनुसार फैसला लिया जाएगा। दरसअसल एनडीए ने 25 से 30, फिर से नीतीश के नारे पर बहुमत लिया है। इसका रिफलेक्शन तब दिखा जब नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर सामने आई।

पार्थ पवार ने राज्यसभा सदस्य के रूप में ली शपथ, उपराष्ट्रपति ने दिलाई शपथ

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पार्थ पवार गुरुवार को आधिकारिक रूप से राज्यसभा के सदस्य बन गए हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने गुरुवार को संसद भवन में पार्थ अजित पवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। एनसीपी के पार्थ पवार महाराष्ट्र से निर्वाचित होकर राज्यसभा पहुंचे हैं। गौरतलब है कि पार्थ पवार महाराष्ट्र के एक प्रमुख राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। वे दिवंगत अजित पवार के पुत्र हैं और शरद पवार के पोते हैं। अजित पवार महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री थे। इसी साल एक विमान दुर्घटना में अजित पवार का निधन हो गया था, जिसके बाद राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। अजित पवार के निधन के कुछ ही समय बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने पति के निधन के कुछ दिनों बाद ही महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली और इसके साथ ही पार्टी की जिम्मेदारियां भी संभालीं। इससे पहले सुनेत्रा पवार राज्यसभा की सदस्य थीं, लेकिन बाद में उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया ताकि वे राज्य सरकार में अपनी नई भूमिका निभा सकें। सुनेत्रा पवार के इस्तीफे के कारण राज्यसभा की जो सीट खाली हुई, उसी सीट पर पार्थ पवार को निर्वाचित किया गया। यह दिल्ली में उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है।

जीओएम की तीसरी बैठक में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल व उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति पर विशेष ध्यान

नई दिल्ली, (एजेंसी)। पश्चिम एशिया में लगातार बदलते हालात के बीच भारत सरकार पूरी तरह सतर्क और सक्रिय बनी हुई है। इसी क्रम में आज बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (जीओएम) की तीसरी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में क्षेत्र की मौजूदा स्थिति और उसके भारत पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी समेत कई वरिष्ठ मंत्री व अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान रक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार देश के भीतर आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि रसोई गैस (एलपीजी), पेट्रोल, डीजल और किसानों के लिए उर्वरकों की आपूर्ति लगातार बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही देशभर में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई को सुचारु रखने के लिए प्रभावी व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने यह भी बताया कि सरकार संभावित संकटों से निपटने के लिए पहले से ही तैयारियों को मजबूत कर रही है। उनका कहना था कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए सतत निगरानी और समयानुसार निर्णय लेना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार की भूमिका को भी इस दौरान रेखांकित किया गया। कहा गया कि सरकार देशवासियों को अंतरराष्ट्रीय संघर्षों के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए लगातार प्रभावी कार्य कर रही है और हर स्तर पर समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पहले, 2 अप्रैल को नई दिल्ली के कर्तव्य भवन–2 में इसी समूह की दूसरी बैठक आयोजित की गई थी।

उत्तर को फायदा, दक्षिण की आवाज दबाने की साजिश : स्टालिन

तमिलनाडु, (एजेंसी)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के उद्देश्य से प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने इस कदम को सत्ता का पुनर्गठन बताया है। 31 जनवरी, 2026 को एक पोस्ट में स्टालिन ने चेतावनी दी कि यदि परिसीमन 2011 की जनगणना के आधार पर किया जाता है, तो उत्तर भारतीय राज्यों को आवंटित सीटों की संख्या लगभग दोगुनी हो जाएगी, जबकि दक्षिण भारतीय राज्यों के पास लोकसभा की लगभग 24 प्रतिशत सीटें रह जाएंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम (डीएमके) महिला आरक्षण का समर्थन करती है, लेकिन सीटों की कुल संख्या बढ़ाने का विरोध करती है। स्टालिन ने लिखा कि यह सुधार नहीं, बल्कि सत्ता का पुनर्गठन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार संसद की नींव को ही धीरे–धीरे खोखला कर रही है। बहस और जवाबदेही के लिए एक जीवंत मंच को एक खोखले अनुष्ठान में तब्दील किया जा रहा है, एक ऐसा मंच जहां सदस्यों को बोलने या अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करने का उचित समय भी नहीं मिल पाता। सीटों में वृद्धि का यह प्रस्ताव उनके अपने नारे न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन का सीधा खंडन है। इससे केवल खर्च बढ़ेगा, करदाताओं पर बोझ बढ़ेगा और संसदीय कार्यप्रणाली की गुणवत्ता कम होगी। संविधान के अनुच्छेद 1 का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 1 की भावना के भी विरुद्ध है, जो भारत को राज्यों का संघ बताता है। राज्यों की आवाजों को नजरअंदाज करना और सार्थक परामर्श को दरकिनार करना लोकतांत्रिक नहीं है। यह एकाधिकारवादी अतिक्रमण है जो भारत के संघीय और बहुलवादी स्वरूप को कमजोर करता है। स्टालिन ने अन्य दक्षिणी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का समर्थन किया और परिसीमन प्रक्रिया को जनसंख्या नियंत्रण में सफल राज्यों के लिए दंडात्मक बताया। उन्होंने कहा कि इससे भी अधिक चिंताजनक बात यह है कि यह प्रक्रिया स्पष्ट रूप से प्रतिनिधित्व को बिगाड़ेगी ।

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने की पूजा, लोगों से वोट डालने का किया आह्वान

असम, (एजेंसी)। वोटिंग के बीच आस्था और लोकतंत्र का संगम सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने की पूजा, लोगों से वोट डालने का किया आह्वान 126 सदस्यों वाली असम विधानसभा के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। इसी बीच, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपने घर पर विशेष पूजा अर्चना की और भगवान से आशीर्वाद मांगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपने घर पूजा करने का एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, "प्रभु का आशीर्वाद और जनता के विश्वास का संकल्प लेकर, असम के उज्ज्वल भविष्य की ओर।" इससे पहले, उन्होंने एक पोस्ट में लिखा, "आज असम में मतदान हो रहा है। एक बेहतर असम के निर्माण की दिशा में हर आवाज और हर वोट मायने रखता है। लोकतंत्र के इस पर्व के अवसर पर मैं सभी से आग्रह करता हूं कि आप बड़ी संख्या में बाहर निकलें और मतदान करें, ताकि लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सके और असम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके।" 126 सदस्यों वाली असम विधानसभा के लिए यह चुनाव बेहद अहम है, जिसमें भाजपा अपनी सत्ता बरकरार रखने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस को सरकार में वापसी की उम्मीद है। यह चुनाव 2023 में इस पूर्वोत्तर राज्य में हुए परिसीमन के बाद पहला चुनाव है। असम में कुल 722 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें 59 महिलाएं शामिल हैं।

ममता बनर्जी के प्रचार पर रोक लगाने की मांग, भाजपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत

कोलकाता, (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए उनके चुनाव प्रचार पर एक निश्चित अवधि के लिए रोक लगाने की मांग की है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री के कुछ बयानों से केंद्रीय सुरक्षा बलों के खिलाफ हिंसा भड़काने की आशंका पैदा हुई है। भाजपा ने बुधवार देर शाम को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भेजे पत्र में आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने चुनाव के दौरान राज्य में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए हैं, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। शिकायत में कहा गया है कि सात अप्रैल को एक जनसभा में ममता बनर्जी ने कथित तौर पर कहा था कि ष्सीआरपीएफ की 200 गाड़ियां लोगों पर हमला करने आ रही हैं।ष भाजपा के अनुसार, इस तरह का बयान जनता के बीच भय का माहौल बनाने और सुरक्षा बलों के प्रति अविश्वास पैदा करने वाला है। इसके अलावा भाजपा ने तीन अप्रैल को दक्षिण दिनाजपुर जिले के हरिरामपुर में हुई एक अन्य सभा का भी उल्लेख किया, जहां मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया था कि केंद्रीय बलों के वाहनों के माध्यम से धन लाया जा रहा है। भाजपा का कहना है कि इस तरह के आरोप केंद्रीय बलों की निष्पक्षता और संवैधानिक भूमिका पर सवाल खड़े करते हैं। पार्टी ने अपने पत्र में कहा कि इस प्रकार के बयान कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं, मतदाताओं में डर पैदा कर सकते हैं और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता को कमजोर कर सकते हैं। भाजपा ने चुनाव आयोग से मांग की है ।

भारतीय केशरिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कृष्ण श्रीवास्तव कायस्थ रत्न सम्मान से हुए सम्मानित

(दीपक श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

लखनऊ। शुक्रवार को भगवान श्री चित्रगुप्त धाम वार्षिक उत्सव का आयोजन बड़े ही भव्य समारोह के बीच सम्पन्न हुआ।इसका आयोजन लखनऊ स्थित श्री चित्रगुप्त धाम, झूले लाल वाटिका गोमती नदी तट पर किया गया।इस मौके पर कार्यक्रम का शुभारम्भ विभिन्न राजनैतिक तथा गैर राजनैतिक दलों से जुड़े कायस्क समाज की लोगो की मौजूदगी में मुख्य अतिथि के रूप में आए लखनऊ के कायस्थ समाज से जुड़े प्रतिष्ठित समाजसेवी व भारतीय केसरिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कृष्ण श्रीवास्तव ने कायस्थ के शिरोमणि भगवान चित्रगुप्त के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलित कर किया।इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आए भारतीय केसरिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कृष्ण श्रीवास्तव तथा वहां पर उपस्थित कायस्थ समाज से जुड़े लोगों ने अपने आराध्य भगवान श्री चित्रगुप्त का विधिवत पूजन तथा आरती किया।इस मौके पर आयोजक मंडल के पदाधिकारियों तथा सदस्यों द्वारा भारतीय केसरिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज कृष्ण श्रीवास्तव द्वारा कार्य समाज की विकास के लिए लगातार किए जा रहे सराहनीय कार्य के चलते उन्हें कायस्थ रत्न सम्मान से सम्मानित किया।इस मौके पर मनोज कृष्ण श्रीवास्तव ने कायस्थ समाज के लोगो को सम्बोधित करते हुये कहा कि आज से नहीं आदिकाल से कायस्थ समाज की गिनती बुद्धिजीवियों में होती रही है और इसी के चलते समाज के विभिन्न ऊचे व महत्वपूर्ण पदों पर, राजनीतिक साहित्यिक, कला विज्ञान खेल सहित अन्य प्रमुख क्षेत्र में अहम भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं।कहा कि अगर कायस्थ समाज मजबूत रहेगा तो हम सभी समाज में अपनी एक अलग प्रतिष्ठा वाली पहचान कायम कर सकते हैं।कहा की हमारी एकता ही उसकी ताकत है ।

संपादकीय

कॉलेजियम को लेकर बढ़ रहे असंतोष

कॉलेजियम सिस्टम के पक्ष में यही दलील दी जाती है कि जजों की नियुक्ति एवं तबादले सरकार के हाथ में चले गए, तो न्यायपालिका में राजनीतिक हस्तक्षेप होने लगेगा। मगर क्या कॉलेजियम ऐसे दखल से जजों को बचा पा रहा है? सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल तो पुराने हैं, लेकिन अब इन्हें सर्वोच्च न्यायपालिका के अंदर से उठाया जा रहा है, तो स्पष्टतरू इसे अधिक गंभीरता से लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के दो जजों– दीपांकर दत्त और मनमोहन ने इस व्यवस्था के संचालन को लेकर गंभीर टिप्पणियां की हैं। दोनों की शिकायतें अलग–अलग हैं, लेकिन उससे कॉलेजियम को लेकर बढ़ रहे असंतोष की झलक मिलती है। जस्टिस दत्त ने कहा कि जिन जजों ने साहस एवं नैतिक दृढ़ता का परिचय दिया, कॉलेजियम उन्हें संरक्षण देने में नाकाम रहा। उन्होंने चेताया कि ऐसी घटनाओं से सिद्धांतों को तरहीज देने वाले जज हतोत्साहित हो सकते हैं। न्यायमूर्ति मनमोहन ने कॉलेजियम के प्रति हाई कोर्ट के जजों में बढ़े अविश्वास की चर्चा की। कहा कि न्यायिक नियुक्तियों के मामले में हाई कोर्ट से आई सिफारिशों को अहमियत ना दिए जाने की शिकायत गहरा गई है, इसलिए कॉलेजियम को इस पर आत्म–निरीक्षण करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉलेजियम और केंद्र सरकार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के प्रति संदेह का रुख रखते हैं। तो मुद्दा यह है कि कॉलेजियम अगर कर्त्तव्यनिष्ठ जजों को संरक्षण नहीं दे सकता, तो फिर उसके होने का औचित्य क्या है? ये प्रणाली खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले से स्थापित की और इसमें बदलाव की कोशिशों को वह नाकाम करता रहा है। इसके पक्ष में यही दलील दी जाती है कि जजों की नियुक्तियांध् तबादले सरकार के हाथ में चले गए, न्यायपालिका में राजनीतिक हस्तक्षेप की गुंजाइश बन जाएगी। मगर अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी संकेत दे रहे हैं कि प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाला कॉलेजियम सियासी दखल से जजों को संरक्षण नहीं दे पा रहा है। कॉलेजियम के पीछे मुख्य धारणा यही है कि इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि न्यायपालिका पूर्ण स्वतंत्रता से काम कर सके। मगर, ऐसा तभी संभव है, जब संस्था की अंदरूनी कार्य–प्रणाली आम–सहमति और व्यापक भागीदारी से प्रेरित हो। उच्चतम न्यायालय के पांच जज बाकी सबकी सिफारिशों की अनदेखी करने लगें, तो फिर इस व्यवस्था के लोकतांत्रिक स्वरूप पर प्रश्न खड़े होंगे। दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज ऐसा ही हो रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पश्चिमी बंगाल अग्नि परीक्षा

अजय दीक्षित

23 और 29 अप्रैल को होने वाले पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष महत्व रखते हैं इन चुनावों की उतनी ही अहमियत है जितनी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की होती है बल्कि उससे इस मायने में अधिक है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी बंगाल में अटलविहारी वाजपई के समय से जनाधार जुटाने में लगी है। अटलजी के मंत्री परिषद में तपन सिकदर पहली बार राज्य मंत्री 1999 में बने थे।तब से भारतीय जनता पार्टी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है।2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 04 सीट मिली थी लेकिन 2016 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 03 सीट मिली पर वोट शेयर 10 फीसदी था ।तब पश्चिमी बंगाल में सीपीएम, कांग्रेस दूसरे और तीसरे स्थान पर थी । तृणमूल कांग्रेस सत्ता में बैठी और ममता बनर्जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी। उस के बाद पश्चिमी बंगाल के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को गंभीरता से लिया और 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा को 39 फीसदी वोट और 42 में से 18 सीट मिली थी सीपीएम,कांग्रेस का एक एक सांसद चुना गया था यही से भारतीय जनता पार्टी की पश्चिमी बंगाल यात्रा शुरू हुई।सीपीएम का वोट शेयर मात्र 8 फीसदी पर आ गया और कांग्रेस का 03 फीसदी।2024 के लोकसभा और 2021 विधानसभा चुनाव में 77 विधायक जीतकर आए।वोट शेयर 39 फीसदी मिला । उल्लेखनीय यह रहा कि नंदीग्राम से भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया। इन चुनावों में ममता बनर्जी ने बंगाल अस्मिता का मुद्दा उठाया और वह कामयाब रहा था लेकिन इस बार भाजपा ने रणनीत बदलकर ममता बनर्जी की सरकार को केंद्रित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव की अपने हाथ में ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता, मुर्शिदाबाद की रैली में राज्य के विकास, महिलाओं की स्थिति, सरकार का भ्रष्टाचार, तृणमूल कांग्रेस की मनमानी,को मुख्य रूप से उठाया है । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव बहुत मायने रखता है। पश्चिमी बंगाल से 2029 लोकसभा चुनाव का रास्ता निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता कि 2029 में भाजपा अकेले दम पर 350 सीट जीते उसके लिए पश्चिमी बंगाल में 42 लोकसभा सीट पर भी उनकी नजर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय मजदूर संघ, और विद्या भारती,बनवासी कल्याण परिषद,सेवा भारती, संस्कृत भारती,आदि बुनियादी संगठनों का फैलाव भी इस विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। पश्चिमी बंगाल में अवैध मुस्लिम, बांग्लादेशी घुसपैठ,सीमांत प्रदेश होने के कारण सामरिक विषय भी मुख्य मुद्दा है। चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 43 से 45 तक वोट शेयर करती है तो उसे पूर्ण बहुमत मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी का एक तबका चाहता है कि तुड़मूल के हिंदू समर्थक अगर जरा भी चेते तो बंगाल में सत्ता परिवर्तन करने से कोई रोक नहीं सकता। दूसरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एस आई आर को मुख्य मुद्दा बनाया है। लेकिन इस मुद्दे हवा निकल रही है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने उनके अनुरोध को स्वीकार न्यायाधीश को काम पर लगाया है।मालदा में कुछ मुस्लिम ने उन पर ही हमला कर दिया है।अबकी बार चुनाव आयोग भी विशेष तैयारी से चुनाव कराने जा रहा है।उसने प्रत्येक मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरा लगाया और उसकी देखभाल अनुविभागीय अधिकारी करेगा ।दो चरणों होने वाले चुनाव में बेहिसाब अर्धसैनिक बलों की तैनादगी की गई है। कोलकाता से प्रकाशित टाइम्स ऑफ इंडिया में शीतल पाल सिंह कहते हैं कि इस बार के चुनावों में ममता बनर्जी उतनी कॉन्फिडेंट नहीं है।वे कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत आई तो राज्य का बुनियादी ढांचे बदलेगा । तपन दास गुप्ता जो बंगाल के प्रमुख प्रकाशित बंगाल टाइम्स में कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह अच्छा है कि सीपीएम, कांग्रेस का कोई विशेष असर नहीं है लेकिन यह भी है कि मुस्लिम मतों का विभाजन नहीं हो रहा है जिससे ममता बनर्जी को लाभ होगा लेकिन इन पार्टियां के हिंदू समर्थक भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे।

कहां गए शांति के कपोत उड़ाने वाले

अशोक

आज की दुनिया बारूद से धधक रही है। रूस–यूक्रेन से लेकर मध्य पूर्व के रेगिस्तानों तक, हर तरफ मिसाइलों की गूँज है। शांति की बाते अब सुनाई नहीं देतीं। शांति के कपोत उड़ाने वाले दिखाई देने बंद हो गए। युद्ध की विभिषिका के विरोध में प्रदर्शन करने और मोमबत्ती जलाने वाले अब सड़कों से गायब है। युद्ध के विरोध के स्वर धीमे ही नही हुए, पूरी तरह खामोश हो गए। बुद्ध के संदेश अब किताबों में ही बंद होकर रह गए है। युद्धों के विरोध की कही से बात नही उठ रही। दुनिया में शांति स्थित करने के लिए बने संयुक्त राष्ट्रसंघ के मुंह पर टेप चिपक गया। वह देख सकता है। न कुछ बोल सकता है। न आदेश कर सकता है। विडंबना देखिए कि इक्कीसवीं सदी में हम मंगल पर बस्तियां बसाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीन के चंद टुकड़ों और आपसी वर्चस्व के लिए हजारों बेगुनाहों का खून बहाने से भी पीछे नहीं हट रहे। युद्ध चाहे रूस और यूक्रेन के बीच हो, या इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव हो। जीत के झंडे चाहे जिस देश के हाथ आएं, हारती हमेशा मानवता है। इन युद्ध में विजयी कोई भी हो, सदा पराजित तो मानव होती है। मरती बस इंसानियत है। इतिहास गवाह है कि युद्ध कभी समस्या का समाधान नहीं रहा, बल्कि यह नई समस्याओं का जन्मदाता है। रूस–यूक्रेन युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई बार कहा कि दुनिया को युद्ध की नहीं, बुद्ध की जरूरत है। कई मंचों से उन्होंने यह मांग उठाई, किंतु किसी भी देश ने शांति का समर्थन नहीं किया। सब देश गूंगे बन कर रह गए। आज भी ये ही हाल है। मरता ईरान खाड़ी के उन देशों पर मिसाइल और ड्रोन दाग कर तबाही मचा रहा है, जिनमे अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं। अपनी बरबादी होते देख ये देश ईरान पर अमेरिकी हमलों का उस तरह विरोध नही कर रहे, जिस तरह कि करना चाहिए। रूस–यूक्रेन युद्ध के समय जहाँ वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा संकट को जन्म दिया तो मध्य पूर्व (इजराइल–हमास–ईरान) के संघर्ष ने दुनिया को धार्मिक और कूटनीतिक ध्रुवीकरण के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। इन लड़ाइयों में टैंकों की गड़गड़ाहट के बीच जो आवाज दब जाती है, वह हैकृएक मासूम बच्चे की चीख और एक बेबस माँ की कराह। युद्ध की सबसे बड़ी कीमत वे लोग चुकाते हैं जिनका राजनीति या सत्ता की लालसा से कोई लेना–देना नहीं होता। यूक्रेन के कीव से लेकर गाजा की गलियों और ईरान के गांव तक तक, हजारों औरतें और बच्चे मौत की नींद सो चुके हैं। जो उम्र खिलौनों से खेलने की थी, उस उम्र में बच्चे बमों के धमाकों को पहचानना सीख रहे हैं। हजारों बच्चे अनाथ हो चुके हैं और लाखों का भविष्य मलबे के नीचे दब गया है। युद्ध के दौरान महिलाओं को न केवल विस्थापन का दंश झेलना पड़ता है, बल्कि वे शारीरिक और मानसिक हिंसा का सबसे आसान लक्ष्य बनती हैं। युद्ध केवल इंसान को नहीं मारता, वह सदियों से बनी–बनाई सभ्यताओं और बुनियादी ढांचे को भी नष्ट कर देता है। स्कूलों, अस्पतालों और रिहायशी इमारतों पर गिरते बम यह दर्शाते हैं कि आधुनिक समाज कितना ष्असंवेदनशीलष हो चुका है। जब एक अस्पताल पर मिसाइल गिरती है, तो वह केवल ईंट–पत्थर की इमारत नहीं ढहती, बल्कि इंसानियत की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। इन लड़ाइयों का असर केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है। रूस–यूक्रेन संघर्ष ने दुनिया भर में अनाज की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ दिया। इससे गरीब देशों में भुखमरी का खतरा बढ़ गया। ईंधन की बढ़ती कीमतें और खाद्य पदार्थों की कमी ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जो खरबों डॉलर शिक्षा, स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में खर्च होने चाहिए थे, वे आज आधुनिक हथियार और मिसाइलें बनाने में झोंके जा रहे हैं। युद्ध का एक और खामोश शिकार हमारा पर्यावरण है। हजारों टन गोला–बारूद का इस्तेमाल वायुमंडल को जहरीला बना रहा है। जंगलों की आग, समुद्री प्रदूषण और जमीन में ध्सें बारूदी सुरंग आने वाली कई पीढ़ियों के लिए मौत का जाल बिछा रहे हैं। हम जिस धरती को बचाने की कसमें खाते हैं, उसी को युद्ध की आग में झोंक रहे हैं। संसाधनों को बरबाद कर रहे हैं। जब हम टीवी पर बमबारी के दृश्य देखते हैं और उन्हें केवल एक ष्न्यूज अपडेटष की तरह छोड़ देते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारे भीतर की इंसानियत मर चुकी है। युद्ध हमें क्रूर बना देता है। हम मौतों को केवल श्आंकड़ोंश में गिनने लगते हैं। घृणा का यह बीज जो आज बोया जा रहा है, वह भविष्य में और अधिक कट्टरपंथ और आतंकवाद को जन्म देगा। अमेरिका आज दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह बन गया है। उसने इराक पर यह कह कर हमला किया था कि उसके पास कैमिकल और अन्य घातक शस्त्र है। इराक हार गया। सद्दाम हुसैन पकड़े ही नही गए, उन्हें फांसी हो गई, किंतु अमेरिका इराक से कुछ भी बरामद नही कर पाया। उसका सब झूंठा प्रचार रहा। अब ईरान पर यह कह कर इजरायल और अमेरिका ने हमला किया कि वह परमाणु बम बनाने के नजदीक है। उसकी इस शक्ति को खत्म करना है। हमले जारी है। इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मीडिया से बात करते हुए अपने मन की बात कह दी कि उसे ईरान के तेल पर कब्जा करना है। तीन जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने एक सैन्य ऑपरेशन के दौरान वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को उनके देश (कराकस) से गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई नार्को–आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी के आरोपों के बाद की गई। इसके बाद उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया। बहाना मादक पदार्थों की तस्करी रोकना था किंतु अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि वेनेजुएला का तेल वे बेचेंगे। उनकी मर्जी से बिकेगा। इस सब का मतलब साफ है कि दुनिया के संसाधनों पर अमेरिका की नजर है। वह किसी ने किसी बहाने उन पर कब्जा करना चाहता है। पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा है कि अगर थोड़ा और समय मिला तो अमेरिका होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोल सकता है और वहां से तेल लेकर बड़ा मुनाफा कमा सकता है। उनके इस बयान ने पहले से चल रहे संघर्ष को और संवेदनशील बना दिया है। फिलहाल ईरान ने इस अहम समुद्री रास्ते को बंद कर दिया है। इस कारण दुनिया भर में तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है और कीमतों में तेजी देखी जा रहीयह संघर्ष अब सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा है। अमेरिका और इस्राइल ने ईरान और लेबनान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इसके जवाब में ईरान ने भी कई खाड़ी देशें पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं।

अमेरिका के लिए ईरान से अहम ये छोटा देश, शांतिवार्ता छोड़ जहां प्रचार करने पहुंचे वेंस

अभिनय

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डी वांस हंगरी पहुंचे हैं, जहां जल्द ही बड़ा चुनाव होने वाला है। वे वहां के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बान का समर्थन करने गए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम चाहते हैं कि ऑर्बान चुनाव क्योंकि वे उनकी सोच, राष्ट्रवाद, सख्त इमीग्रेशन और पारंपरिक मूल्यों के करीब है। विक्टर ऑर्बान, ने 2010 से सत्ता में है और मजबूत नेता माने जाते है। पीटर माज्यार, जो पहले ऑर्बान के करीबी थे, पर अब उनके खिलाफ खड़े हैं। मैग्यार के मुद्दे पर जनका का समर्थन जुटा रहे हैं। हंगरी का चुनाव न केवल उस देश के लिए, बल्कि पूरे यूरोप और वैश्विक राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बान की नीतियों के कारण हंगरी का यूरोपीय संघ के साथ अक्सर टकराव रहता है। उन पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप है, जिसकी वजह से EU ने हंगरी की अरबों डॉलर की फंडिंग रोक दी है। यदि चुनाव के बाद वहां सत्ता परिवर्तन होता है, तो हंगरी और यूरोप के संबंधों में नई गर्माहट आ सकती है और रुकी हुई आर्थिक मदद मिलने का रास्ता साफ हो सकता है, जिससे पूरे यूरोप की एकता मजबूत होगी। रूस–यूक्रेन युद्ध के नजरिए से भी यह चुनाव काफी अहमियत रखता है। हंगरी, जो कि नाटो और ईयू दोनों का सदस्य है, ओर्बान के नेतृत्व में रूस के प्रति थोड़ा नरम रुख अपनाता रहा है। उन्होंने कई बार यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य मदद और रूस पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों में अड़ंगा डाला है। ऐसे में चुनाव का परिणाम यह तय करेगा कि भविष्य में यूक्रेन को मिलने वाली यूरोपीय मदद कितनी आसान होगी। अगर नई सरकार आती है, तो हंगरी का झुकाव पूरी तरह पश्चिम की ओर हो सकता है, जो रूस के लिए एक कूटनीतिक झटका होगा। टूप और उनकी टीम मानती है कि ऑर्बान ने एक ऐसा मॉडल बनाया है जिसमें मजबूत नेता, कम इमिग्रेशन और नेशनलिस्ट सोच होती है। वे चाहते हैं कि यूरोप मे ऐसे ही और नेता आएँ। इसलिए अमेरिका (ट्रंप के प्रभाव वाला पक्ष) ऑर्बान को जिताना चाहता है। रूस भी चाहता है कि ऑर्बान सत्ता में रहे, क्योंकि वे रूस के खिलाफ कड़े कदम (जैसे पाबंदिया) रोकते रहे है। यूक्रेन को मिलने वाली मदद में अड़चन डालते है। रूस के लिए ऑर्बान यूरोप के अंदर एक मजबूत साथी है। वैश्विक स्तर पर हंगरी की राजनीति अब अमेरिका और रूस जैसी बड़ी शक्तियों के बीच शक्ति संतुलन का केंद्र बन गई है। एक तरफ जहां रूस और चीन हंगरी के जरिए यूरोप में अपना प्रभाव बनाए रखना चाहते हैं, वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी चाहते हैं कि हंगरी पूरी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों और पश्चिमी गठबंधन का साथ दे। सरल शब्दों में कहें तो, इस चुनाव का नतीजा केवल हंगरी की किस्मत नहीं बदलेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि यूरोप की सुरक्षा और कूटनीति में रूस का हस्तक्षेप कितना कम या ज्यादा होगा। यूक्रेन चाहता है कि ऑर्बान हारे, क्योकि वे उसके खिलाफ बोलते रहे है। यूरोपियन यूनियन भी उनसे परेशान है, क्योंकि ऑर्बान कई फैसलों में रुकावट डालते है। अगर माज्यार जीतते है, तो ईयू और यूक्रेन को राहत मिलेगी। जासूसी और लीक के आरोप लग रहे है गैस पाइपलाइन के पास विस्फोट जैसी घटनाएं हुई है सरकार और विपक्ष एक–दूसरे पर साजिश के आरोप लगा रहे है। ऑर्बान ने 16 साल में सिस्टम को अपने हिसाब से मजबूत किया है और वे कभी नहीं हारे। अगर वे हारते है और सत्ता छोड़ने से मना करते है, तो बड़ा राजनीतिक संकट हो सकता है। इसलिए यह चुनाव अमेरिका, रूस, यूक्रेन के लिए भी अहम है। बहरहाल,

चुनाव का नतीजा यह तय करेगा कि हंगरी अपनी लोकतांत्रिक संस्थाओं को सुधारकर के साथ तालमेल बिठाएगा या अपनी अलग राह पर चलते हुए गठबंधन में दरार पैदा करेगा। यदि नई सरकार आती है, तो रूस पर प्रतिबंध लगाने और यूक्रेन को सैन्य सहायता देने के यूरोपीय फैसलों में आने वाली बाधाएं खत्म हो सकती हैं। विक्टर ओर्बान के सत्ता में बने रहने से रूस को यूरोप के भीतर एक भरोसेमंद सहयोगी मिलता रहेगा, जबकि सत्ता परिवर्तन मास्को के कूटनीतिक प्रभाव को कमजोर कर देगा। हंगरी का चुनाव यह निर्धारित करेगा कि पश्चिमी सैन्य गठबंधन में एकता बनी रहेगी या हंगरी के ष्रूस–हितैषीष रुख के कारण अमेरिका को अपनी सुरक्षा रणनीति बदलनी पड़ेगी। सत्ता में बदलाव से हंगरी को से मिलने वाली अरबों यूरो की रुकी हुई फंडिंग मिल सकती है, जिससे न केवल हंगरी की अर्थव्यवस्था संभलेगी बल्कि पूरे यूरोप की आर्थिक एकजुटता भी बढ़ेगी।

भारत की विकास गाथा के केंद्र में महिलाएँ

विजय

भारत की विकास गाथा को अक्सर संख्याओं, विकास दरों, अवसंरचना विस्तार और आर्थिक उपलब्धियों के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेकिन, पिछले दशक का सबसे बड़ा बदलाव आँकड़ों से परे है। यह एक गहरे सामाजिक बदलाव में परिलक्षित होता हैकृमहिलाओं का केवल भागीदार के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्र के भविष्य को आकार देने वाले अग्रिम व्यक्तियों के रूप में उभरना। महिलाओं के नेतृत्व में विकास की ओर यह बदलाव न तो आकस्मिक है और न ही अलग–थलग है। यह एक सोच–समझकर किये गये सतत प्रयास का परिणाम है, जो जीवन के हर चरण में महिलाओं को समर्थन देने के लिए एक सक्षम इकोसिस्टम का निर्माण करता है। लड़की के जन्म से लेकर उद्यमी, पेशेवर, या सार्वजनिक प्रतिनिधि के रूप में उसकी यात्रा तक, यह दृष्टिकोण समग्र, सतत और परिवर्तनकारी रहा है। राजनीतिक भागीदारी में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया है। निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या 12,14,885 है, जिनकी कुल 24,41,781 निर्वाचित प्रतिनिधियों में हिस्सेदारी 49.75 प्रतिशत हैकृइस प्रकार, महिलाएँ जमीनी स्तर पर शासन में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। इस क्रम में, नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी उपलब्धि है, जिसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक–तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। यह उच्च विधायी क्षेत्रों में महिलाओं की नेतृत्व क्षमता को मजबूत करने में राष्ट्र की अडिग प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है। इस ऐतिहासिक सुधार की वास्तविक क्षमता केवल इसके प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से ही हासिल की जा सकती है। अधिनियम की प्रावधानों को जल्द से जल्द लागू करने की आवश्यकता है, ताकि महिलाओं की आवाज को सिर्फ मान्यता ही न मिले, बल्कि देश की लोकतांत्रिक संरचना में इसे संस्थागत रूप से समाहित किया जा सके। इसके जल्द लागू होने से न केवल समावेशी शासन को गति मिलेगी, बल्कि यह बेहतर प्रतिनिधित्व और न्यायसंगत राजनीतिक परिदृश्य के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करेगा। दशकों तक, लैंगिक पक्षपात ने भारत के जनसांख्यिकीय और सामाजिक संकेतकों को प्रभावित किया। आज, वह कहानी धीरे–धीरे फिर से लिखी जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी पहलों ने गहरी जड़ें जमा चुकी मानसिकताओं को चुनौती देने और लड़की के मूल्य को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। इसका प्रभाव राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस–5) में दिखाई देता है, जिसमें 1,000 पुरुषों पर 1,020 महिलाओं का लैंगिक अनुपात दर्ज किया गया है, जो सिर्फ संख्यात्मक सुधार ही नहीं बल्कि सामाजिक बदलाव का भी संकेत देता है। मिशन इंद्रधनुष जैसे कार्यक्रम जीवन के प्रारंभिक चरण में पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करते हैं। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी, पोषण 2.0, तथा पोषण अभियान के प्रयास कुपोषण का समाधान करते हैंकृयह मानते हुए कि स्वस्थ बचपन, सशक्त वयस्कता की ओर पहला कदम होता है। माताओं के लिए, संस्थागत समर्थन में काफी विस्तार हुआ है। पीएमएमवीवाई के तहत, 4.28 करोड़ से अधिक महिलाओं को 20,149 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि वितरित की गयी है, जो गर्भावस्था के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करती है। महिलाएं केवल भाग ही नहीं ले रही हैंकृवे नेतृत्व भी कर रही हैं। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में संस्थापक और निर्णयकर्ताओं के रूप में महिलाओं की भूमिका में लगातार वृद्धि हो रही है और वे नवाचार और उद्यम में भी योगदान दे रही हैं। इस परिवर्तन में वित्तीय समावेश ने अहम भूमिका निभाई है। पीएमएमवाई के तहत, 40 लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के 57.79 करोड़ ऋण प्रदान किए गए हैं, जिनमें लगभग 66 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं। प्रत्येक ऋण केवल वित्तीय सहायता का ही नहीं, बल्कि महिलाओं की आकांक्षाओं में विश्वास का भी प्रतीक है। इसके पूरक रूप में, जन धन योजना के तहत वित्तीय समावेश और गहरा हुआ है, जिसके अंतर्गत 57.93 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें से 32.29 करोड़ (55.7 प्रतिशत) महिलाओं के हैं। जमीनी स्तर पर, परिवर्तन का पैमाना और भी अधिक प्रभावशाली है। लगभग 10 करोड़ महिलाओं को 90 लाख से अधिक स्वयं–सहायता समूहों में संगठित किया गया है, जिससे सामूहिक सहनशीलता, वित्तीय स्वतंत्रता और सामाजिक आत्मविश्वास को बढ़ावा मिला है। इस इकोसिस्टम ने 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में उभरने में सक्षम बनाया है और स्वयं सहायता समूहों को 12.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बैंक ऋण प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, 84 लाख ग्रामीण महिलाएं उद्यमी बन चुकी हैं, जबकि 5 करोड़ महिला किसानों ने उन्नत और सतत कृषि प्रथाओं में प्रशिक्षण प्राप्त किये हैं। स्वाभाविक रूप से अगला सवाल उठता हैकृक्या सशक्तिकरण, आजीविका से समृद्धि की ओर बढ़ सकता है? लखपति दीदी जैसी पहलों का लक्ष्य आय सृजन को मजबूत करना है, जबकि ड्रोन दीदी पहल, जिसका लक्ष्य 15,000 महिलाओं को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित करना है, एक दूरदर्शी दृष्टिकोण को परिलक्षित करती हैकृग्रामीण महिलाओं को प्रौद्योगिकी–संचालित कृषि इकोसिस्टम में एकीकृत करना। सशक्तिकरण का मतलब रोजमर्रा के बोझ को आसान बनाना भी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 10.56 करोड़ से अधिक धुँआ–रहित रसोई घरों ने स्वास्थ्य में सुधार किया है और कठिनाइयों को कम किया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.8 करोड़ से अधिक शौचालयों के निर्माण ने गरिमा और सुरक्षा में वृद्धि की है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसकी 73 प्रतिशत लाभार्थी महिलाएं हैं, के तहत निर्मित घरों ने स्वामित्व और सुरक्षा को मजबूत किया है। साथ मिलकर ये सभी पहलें दैनिक जीवन में गरिमा की परिभाषा को नए सिरे से स्थापित करती हैं। इसके साथ ही, महिलाएं उन स्थानों में भी प्रवेश कर रही हैं, जिन्हें कभी उनकी पहुँच से बाहर माना जाता था। सशस्त्र बल इस बदलती हुई वास्तविकता को दर्शाते हैं, जहाँ महिलाएँ नेतृत्व और जिम्मेदारी की भूमिकाएँ निभा रही हैं, जिसमें युद्ध क्षेत्र भी शामिल हैं। सवाल अब यह नहीं है कि महिलाएँ सेवा कर सकती हैं या नहीं, बल्कि यह है कि वे कितनी दूर तक नेतृत्व कर सकती हैं। कार्यस्थल सुधारों ने भी इस बदलाव में योगदान दिया है। नयी श्रम संहिताएँ महिला कर्मचारियों को उचित सुरक्षा उपायों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में, जिसमें रात की शिफ्ट भी शामिल है, काम करने में सक्षम बनाकर समावेश को बढ़ावा देती हैं। ये संहिताएँ समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा और सम्मान पर जोर देती हैंकृसुरक्षा से सशक्तिकरण की ओर बदलाव को रेखांकित करती हैं। संस्थागत समर्थन एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने शिकायत निवारण से आगे बढ़कर सक्रिय जुड़ाव और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में भी अपना विस्तार किया है। शी सर्वस जैसी पहल महिला अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन करती हैं, जबकि यशोदा एआई उन्हें उभरते तकनीकी कौशल प्रदान करती है। कैंपस कॉलिंग युवाओं में जागरूकता बढ़ाता है, शी इज अ चेंज मेकर कार्यक्रम जमीनी स्तर पर नेतृत्व क्षमता को मजबूत करता है और महिला जनसुनवाई सुलभ शिकायत निवारण सुनिश्चित करता है।

जौनपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, असम के मुख्यमंत्री के खिलाफ पुतला दहन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर कार्यालय पर हेमंत विश्वा शर्मा के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन असम चुनाव के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके परिवार और राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा के खिलाफ कथित अमर्यादित भाषा के प्रयोग को लेकर किया गया। जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि हेमंत विश्वा शर्मा का चुनाव रद्द किया जाए और उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जाए। साथ ही उनकी तत्काल गिरफ्तारी की भी मांग उठाई गई। पुतला दहन के बाद सभा को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष डॉ. प्रमोद कुमार सिंह ने शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने उन्हें देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में असम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और लूटपाट हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के परिवार ने राज्य के ध न का दुरुपयोग कर विदेशों में निवेश किया है। डॉ. सिंह ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने के बाद मुख्यमंत्री ने कथित रूप से अपना संतुलन खो दिया और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उन्होंने भाजपा सरकार पर चुनाव के दौरान असम पुलिस के दुरुपयोग और आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आरिफ खान ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता का दुरुपयोग और विपक्षी नेताओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का प्रयोग भाजपा की कार्यशैली बन गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ ईडी और सीबीआई जांच की मांग की। आरिफ खान ने कहा कि मुख्यमंत्री की पत्नी रिंकु भुइयां सरमा की विदेशी संपत्तियों, पासपोर्ट और कथित गोल्डन कार्ड की भी जांच कराई जानी चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग से मामले का संज्ञान लेकर तत्काल कार्रवाई करने और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की मांग की ।

जौनपुर में भीषण आग गुमटियां जलकर राख, लाखों का नुकसान, शॉर्ट सर्किट की आशंका

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में लाइन बाजार थाना क्षेत्र के वाजिदपुर तिराहे के पास सिटी टावर से पहले सड़क किनारे बनी गुमटियों में शुक्रवार की भोर करीब 4 बजे भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते कई गुमटियां इसकी चपेट में आ गईं। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने आग लगने की सूचना फायर ब्रिडेग को दिया। घटना की सूचना मिलते ही फायर अधिकारी नागेंद्र द्विवेदी अपनी टीम और दो दमकल गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। आग ने विकराल रूप ले लिया था, जिसे काबू में करने में टीम को घंटों मशक्कत करनी पड़ी। प्रत्यक्षदर्शी कृपावंश जायसवाल ने बताया कि वह सुबह करीब 4 बजे मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे, तभी अचानक आग लगी देखी। उन्होंने तुरंत लोगों को फोन कर सूचना दी और फायर स्टेशन को भी जानकारी दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग से कई दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ है। पीड़ित दयाराम प्रजापति ने बताया कि उनकी नाश्ते की दुकान में आग लगने से करीब 60 से 65 हजार रुपये का सामान जलकर राख हो गया। वहीं, बबलू प्रजापति की गुमटी पूरी तरह से जल गई, जिससे उन्हें काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। पीड़ितों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है।इस संबंध फायर अधिकारी नागेंद्र द्विवेदी ने बताया कि आग लगने के सही कारणों का पता जांच के बाद ही चल पाएगा, हालांकि शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की संभावना जताई जा रही है।घंटों को कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया है।कोई जनहानि नहीं है।

सुबह से ही रिमझिम गिरी बारिश की बूंदे, साथ में ठंडी हवाएं- मौसम हुआ सुहाना

गोरखपुर, (संवाददाता)। मौसम का मिजाज बुधवार की सुबह से ही बदला–बदला सा रहा। तेज हवाओं और गरज–चमक के साथ रिमझिम बारिश सुबह से ही शुरू हो गई। गर्मी के बाद अचानक से बदले इस मौसम में लोगों ने राहत की सांस ली। हल्की बारिश में भी लोग अपने काम को लेकर आते–जाते दिखे। मौसम विभाग ने बुधवार को तेज हवाओं और

गरज–चमक के साथ बारिश की उम्मीद जताई थी। बारिश के कारण तापमान में पांच डिग्री तक गिरावट के आसार हैं। हालांकि इससे गेहूं की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। मौसम वैज्ञानिक कैलाश पांडेय के मुताबिक, बारिश के लिए वायुमंडलीय परिस्थितियां तैयार हो चुकी है। पश्चिमोत्तर के पहाड़ों पर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होकर तिब्बत की ओर बढ़ रहा है। इस बीच पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपरी वायुमंडल में 5000 फीट की ऊंचाई पर एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र भी बन गया है। इसका असर दिखने लगा है। बुधवार को भी तेज गति से हवाएं चलेंगी और आसमान में बादल भी छाने लगेंगे। बूंदाबांदी से लेकर कहीं–कहीं बारिश का अनुमान है। उन्होंने बताया कि मौसम में बदलाव का असर बृहस्पतिवार तक रहेगा।

मतदाता सूची पर सपा का सवाल, चुनाव आयोग पर लगे गंभीर आरोप:आमीक जामोई

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आमीक जामोई ने एसएआर के अंतिम दिन जारी मतदाता सूची को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जौनपुर सहित प्रदेश के किसी भी नागरिक, खासकर पिछड़े, दलित और कमजोर वर्गों के मताधिकार पर कोई आंच न आए। उक्त बातें उन्होंने ने शुक्रवार को यूपी के जौनपुर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के बीच मिलीभगत से बड़े स्तर पर गड़बड़ी की आशंका है, जिसकी झलक पश्चिम बंगाल चुनाव में भी देखने को मिली। उन्होंने कहा कि पार्टी गांव–गांव जाकर सूची की जांच करेगी और यह पता लगाएगी कि किन लोगों के नाम हटाए गए हैं तथा जिनका स्थानांतरण हुआ है, उनके नाम कहां जोड़े गए हैं। पश्चिम बंगाल और असम के चुनावों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेताओं के पास अब ठोस मुद्दों की कमी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपने भाषणों के जरिए माहौल को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, जबकि जनता चुनाव के माध्यम से अपनी पसंद की सरकार चुनती है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वा शर्मा के बयान पर उन्होंने आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की भाषा किसी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देती। उन्होंने कहा उच्चतम न्यायालय को मामले का स्वतः संज्ञान लेने की मांग की। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि असम में कानून–व्यवस्था और विकास की स्थिति चिंताजनक है तथा राज्य में शांति व्यवस्था प्रभावित हो रही है। उन्होंने दावा किया कि इस बार असम और पश्चिम बंगाल की जनता बदलाव के लिए मतदान करेगी। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर बोलते हुए उन्होंने अमेरिका–ईरान और इजरायल से जुड़े घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर तनाव बढ़ रहा है और इसका असर आसपास के देशों पर भी पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की जनता शांति और स्थिरता की पक्षधर है।

विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अन्तर्गत अंतिम मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन जिलाधिकारी ने दिया जानकारी

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र की अध्यक्षता में विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अन्तर्गत अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन के सन्दर्भ में कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेसवार्ता की गयी। जिला निवार्चन अधिकारी के द्वारा बताया गया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र एवं भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि–01.01.2026 के आधार पर जनपद की समस्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण–2026 कार्यक्रम के अन्तर्गत 06 जनवरी 2026 से 06 मार्च 2026 तक दावें एवं आपत्तियां प्राप्त की गई। जनपद में विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण 2026 के पूर्व 1859013 पुरुष मतदाता, 1711692 महिला मतदाता तथा तृतीय लिंग के 146 मतदाता कुल 3570851 मतदाता थे। विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण (एसआईआर–2026) के दौरान 289452 मतदाताओं द्वारा डुप्लीकेट, मृतक, शिफ्टेड आदि होने के कारण गणना प्रपत्र जमा नहीं किये गये। जिन्हें पृथक करते हुये आलेख्य प्रकाशन 06 जनवरी 2026 को 1606024 पुरुष मतदाता, 1375180 महिला मतदाता एवं 104 तृतीय लिंग मतदाता कुल 2981308 मतदाता आलेख्य सूची में प्रकाशित किये गये। आलेख्य प्रकाशित सूची में 289452 मतदाताओं द्वारा अपने परिवार से मैप न किये जाने के कारण तथा 563263 तार्किक विसंगति वाले मतदाता कुल 852715 मतदाताओं को नोटिस तामील करते हुये कुल 09 ईआरओ, 293 ए0ई0आर0ओ0 के माध्यम से सुनवाई करते हुये प्रत्येक मतदाता के प्रपत्रों को जांच करते हुये निस्तारित किया गया। उक्त कार्य में जनपद जौनपुर के कुल 09 विधानसभाओं के 4172 बूथ लेवल अधिकारियों एवं 421 सुपरवाइजरों के सहयोग से सम्पादित किया गया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में प्रत्येक मतदाता के घरों पर पहुंचकर जांच की गई एवं ऐसे मतदाता अथवा उनके सम्बन्धियों के नाम 2003 की मतदाता सूची में नाम अंकित था, को ऑनलाइन ऐप के

माध्यम से प्रपत्रों की जांच करते हुये मतदाता सूची में सम्मिलित किया गया है। विधान सभावार विवरण के अनुसार आलेख्य प्रकाशन के दौरान 132605 पुरुष मतदाता, 121045 महिला मतदाता व तृतीय लिंग 19, कुल 253669 नये मतदाता जोड़े गये। इस प्रकार अन्तिम प्रकाशन दिनांक 10 अप्रैल 2026 को 1732222 पुरुष मतदाता, 1486556 महिला मतदाता एवं तृतीय लिंग के 119 मतदाता कुल 3218897 मतदाता अन्तिम निर्वाचक नामावली में प्रकाशित किये गये हैं। अन्तिम प्रकाशन 10 अप्रैल 2026 से सम्बन्धित की जाने वाली कार्यवाही निम्नवत् है रू– विधानसभा क्षेत्र 364–बदलापुर में 330446, 365– शाहगंज में 381806, 366–जौनपुर में 401871, 367–मल्हनी में 341284, 368–मुंगराबादशाहपुर में 349094, 369–मछलीशहर में 365941, 370–मडियाहू में 313529, 371–जाफराबाद में 350740, 372–केराकत में 384186 मतदाता है। 10 अप्रैल 2026 को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम–1960 के सुंसगत नियमों के अन्तर्गत अन्तिम प्रकाशन निर्धारित प्रारुप–16 पर करते हुये निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय, जिला निर्वाचन कार्यालय तथा समस्त मतदेय स्थलों पर जनसामान्य के निरीक्षण हेतु एक सप्ताह की अवधि के लिये उपलब्ध रहेगी। नियम–22 (ग) के अनुसार अन्तिम प्रकाशन हेतु तैयार निर्वाचक नामावलियों को समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनैतिक दलों को निःशुल्क दो प्रतियों (एक प्रति हार्ड एवं एक प्रति सॉफ्टकापी) में उपलब्ध कराई जा रही है। अन्तिम प्रकाशित निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट https://voters-eci-gov-in/download-eroll\stateCode)S24 पर भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विधान सभा के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित मतदाता सूची को संरक्षित किया गया है। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी परमानंद झा, जिला सूचना अधिकारी मनोकामना राय, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी डॉ अरुण कुमार यादव सहित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के समस्त पत्रकार बंधु उपस्थित रहे।

माध्यमिक शिक्षक संघ का धरना समाप्त, डीआईओएस को सौंपा ज्ञापन

ब्यूरो प्रमुख
विश्व प्रकाश श्रीवास्तव

जौनपुर। यूपी के जौनपुर में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का एक दिवसीय धरना जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर शुक्रवार को सम्पन्न हो गया। जिलाध्यक्ष प्रमोद सिंह के नेतृत्व में शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर डीआईओएस राकेश कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। धरने में सैकड़ों की संख्या में शिक्षक शामिल हुए और अपनी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। जिलाध्यक्ष ने बताया कि 1 अप्रैल 2025 से एनपीएस से ओपीएस में शामिल हुए शिक्षकों के जीपीएफ खातों में कटौती की राशि अब तक अंतरित नहीं की गई है। शासन के निर्देश के बावजूद 31 मार्च तक यह प्रक्रिया पूरी न होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। शिक्षकों ने यह भी आरोप लगाया कि एनपीएस में शामिल शिक्षकों के खातों में तीन से चार महीने बाद भी धनराशि अपडेट नहीं हो रही है। इसके साथ ही बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन केंद्रों पर जलपान मानदेय में अनियमितता, ग्रीष्मकालीन अवकाश में जनगणना ड्यूटी लगाए जाने और जनपद में सिटीजन चार्टर लागू न होने जैसी समस्याएं भी उठाई गईं। संगठन ने जनगणना ड्यूटी के बदले 40 दिन के अर्जित अवकाश की मांग की। प्रांतीय उपाध्यक्ष नरसिंह बहादुर सिंह ने कहा कि जनपद में स्थानीय समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है और कार्यालयों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि विनियमितीकरण की फाइलों को आगे बढ़ाने के नाम पर शिक्षकों और कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। डीआईओएस ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि सभी मांगों पर सकारात्मक विचार किया जाएगा और समस्याओं के समाधान का प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने की बात भी कही। जिलामंत्री दिनेश चक्रवर्ती ने सभी शिक्षकों का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि ज्ञापन की एक प्रति जिलाधिकारी को भी सौंपी जाएगी। इस अवसर पर जयप्रकाश सिंह, रामप्रकाश सिंह, प्रवीण पाण्डेय, विजय सिंह यादव, रामप्रताप विश्वकर्मा, आलोक श्रीवास्तव, डॉ. सुनील सिंह, अवधेश सिंह, प्रशांत पाण्डेय, संजय पाठक, सुजीत चौरसिया, शिव श्याम और अजीत प्रताप सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे।

अब एक साथ नहीं होगी शहर के मुख्य स्कूलों की छुट्टी, जाम से बचने के लिए बनाई गई गाइडलाइन लगेगा जुर्माना

लखनऊ, (संवाददाता)। डीजीपी राजीव कृष्ण ने शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या को दूर करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है। इसमें यातायात विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों व संबंधित थानों के प्रभारियों की जिम्मेदारी भी तय की गई है। साथ ही नो एंट्री, नो पार्किंग, गलत दिशा में ड्राइविंग, अतिक्रमण, ई–रिक्शा संचालन के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। एसओपी में आसपास के दफ्तरों और स्कूलों के छूटने के समय में 15–15 मिनट के अंतराल की सिफारिश भी की गई है। दरअसल, डीजीपी ने मंगलवार को 20 शहरों के 172 मार्गों को ट्रैफिक जाम से मुक्त कराने के लिए रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन स्कीम (सीआरटीसी) की शुरुआत की थी। इसी क्रम में एसओपी जारी की गई है। इसमें रूट मार्शल की तैनाती, यात्रा का समय कम करने का जिक्र है। साथ ही व्यस्त चौराहों व तिराहों के 100 मीटर के क्षेत्र को पूरी तरह खाली रखने को कहा गया है। इस क्षेत्र में किसी भी सवारी तो उतारा या बैठाया नहीं जा सकेगा। अधिक यातायात दबाव वाले क्षेत्रों में पीक ऑवर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती होगी। नो एंट्री का उल्लंघन करने पर 20 हजार रुपये, नो पार्किंग एवं अवैध पार्किंग पर पहली बार में 500 रुपये और उसके बाद 2000 रुपये जुर्माना, गलत दिशा में वाहन चलाने पर 2000 रुपये जुर्माना लेने का निर्देश दिया गया है। अतिक्रमण हटवाने, सड़कों को चौड़ा करने, मुख्य मार्गों को ई–रिक्शा मुक्त क्षेत्र घोषित करने समेत कई अन्य उपाय भी बताए गए हैं। सीआरटीसी योजना के तहत कराए गए सर्वे में राजधानी के दो मुख्य मार्गों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम की हकीकत सामने आई है। बख्शी का तालाब से पॉलीटेक्निक और आलमबाग स्थित अवध चौराहा से दुबग्गा मार्ग के सर्वे से पता चला कि पीक आवर्स में इन रास्तों पर यात्रा का समय न्यूनतम की तुलना में 10 से 15 गुना तक बढ़ जाता है। बख्शी का तालाब से पॉलिटेक्निक मार्ग की कुल लंबाई 16.26 किलोमीटर है। यात्रा में न्यूनतम समय 12.05 मिनट लगता है, जो पीक ऑवर्स में बढ़कर 15 गुना अधिक हो जाता है। अधिकतर दोपहर में 1:30 से 2:30 बजे, शाम 4:00 से 4:30 बजे और 7:00 से 7:30 बजे के बीच जाम लगता है। इसी तरह अवध चौराहा से दुबग्गा की दूरी 10.51 किलोमीटर है। पीक ऑवर्स दोपहर 11:30 से 12:00 बजे, दोपहर 3:00 से 3:40 बजे और रात 11:25 से 11:45 बजे यात्रा करने में 10 गुना से अधिक समय लगता है।

18 वर्षों से फरार डकैती का वारंटी गिरफ्तार, न्यायालय के आदेश पर इटौंजा पुलिस की कार्रवाई

लखनऊ, (संवाददाता)। इटौंजा थाना पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे डकैती के एक वारंटी को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। यह आरोपी पिछले 18 वर्षों से न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने लगातार सुरागरसी और पतारसी के बाद दबिश देकर उसके घर से गिरफ्तार कर लिया।पुलिस के अनुसार विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा वाद संख्या 996ध्08, अपराध संख्या 03ध्2008, धारा 396 भारतीय दंड संहिता, थाना इटौंजा से संबंधित एक वारंटी गुड्डू पुत्र सियाराम, निवासी भन्सारी थाना कोतवाली सदर जनपद लखीमपुर खीरी के विरुद्ध गिरफ्तारी अधिपत्र जारी किया गया था। आरोपी गुड्डू पर डकैती का गंभीर अपराध करने का आरोप है और वह पिछले लगभग 18 वर्षों से फरार चल रहा था।इटौंजा थाना पुलिस टीम द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। पुलिस ने उच्च स्तर की सुरागरसी और पतारसी करते हुए आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी और उसके संभावित ठिकानों की जानकारी जुटाई। इसी क्रम में 08 अप्रैल 2026 को पुलिस टीम ने आरोपी के अंकित पते पर दबिश दी। पुलिस ने गिरफ्तारी अधिपत्र दिखाते हुए आरोपी को उसके घर से हिरासत में ले लिया।पुलिस अधिकारियों के अनुसार आरोपी लंबे समय से न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं कर रहा था और गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी से एक पुराने लंबित मामले में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आरोपी के विरुद्ध आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है और उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

शिशु के मल की फोटो से एप बता देगा बीमारी है या नहीं, लोहिया संस्थान ने तैयार किया एआई आधारित मोबाइल एप

लखनऊ, (संवाददाता)। डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के बाल रोग विभाग ने एक नया मोबाइल एप लॉन्च किया है। यह एप शिशु के मल की फोटो देख बीमारियों का पता लगाएगा। इस नवाचार को पेटेंट भी मिल चुका है। जो जल्द ही प्ले स्टोर पर आएगा। बुधवार को संस्थान के एडमिन ब्लॉक में मुख्य अतिथि और संस्थान के निदेशक प्रो. सीएम सिंह ने लिवर पूप एप को लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि यह भारत का पहला एआई आधारित मोबाइल एप है। इससे शिशुओं को समय पर इलाज मिल पाएगा। बाल हेपेटोलॉजिस्ट एवं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. पीयूष उपाध्याय ने इसे 500 शिशुओं पर तीन वर्ष के अध्ययन के आधार पर तैयार किया है। डॉ. पीयूष ने बताया कि एप बनाने का मुख्य उद्देश्य नवजात शिशुओं को खतरनाक बीमारी बिलीरी एट्रेसिया (पित्तवाहिनी अवरोध) से बचाना है। लॉन्चिंग के दौरान विशिष्ट अतिथि डीन डॉ. प्रद्युमन सिंह, सीएमएस प्रो. विक्रम सिंह, बाल रोग विभाग की अध्यक्ष प्रो. दीप्ति अग्रवाल व अन्य चिकित्सक मौजूद रहे।

विरोधियों पर जीत के लिए कर रहे जाप, सलाखों वाले विभाग में सिपाहियों का दबदब

लखनऊ, (संवाददाता)। यूपी में सत्ता के बदलाव की आहट ने माननीयों का धर्म–कर्म की तरफ रुझान बढ़ा दिया है। एक माननीय तो संकल्प लेने के लिए शक्तिपीठ तक पहुंच गए। वहीं, सलाखों वाले विभाग में तो सिपाहियों का दबदबा हो गया है। वहीं, एक बड़े साहब तो अपने ही महकमे से बेखबर हैं। सूबे की सत्ता में बदलाव की आहट ने कई माननीयों में धार्मिक ज्वार पैदा कर दिया है। ऐसे ही एक माननीय हैं जो महाकाल और उनके पास में ही स्थित विरोधियों पर जीत दिलाने वाली देवी की उपासना में जुट गए हैं। उनकी इस आस्था का खुलासा तब हुआ जब वह खुद एक दिन संकल्प लेने शक्तिपीठ पहुंचे थे। संयोग से उनके एक परिचित मिल गए तो माननीय ने मुंह पर गमछा बांधकर पहचान छिपाने की कोशिश की लेकिन इतने बड़े नेता हैं तो पहचान कैसे छिपेगी। बाद में पुरोहित ने बताया कि माननीय उच्चाटन जाप करा रहे हैं। सलाखों वाला विभाग अलग ही ट्रैक पर है। जहां से सिपाहियों का तबादला, पदोन्नति का काम होता है, उसकी जिम्मेदारी खुद ही उठा रखी है। मतलब दो–तीन सिपाही खुद ही बाबू बन गए। वह खुद अपने लोगों का तबादला व अन्य कार्य करने में जुटे हैं। इससे बाबू बहुत परेशान हैं। इसके पीछे की वजह साहब की शह है। यह शह तीन चार सिपाहियों को दी गई। महकमे के कर्मचारी बेहद परेशान हैं। चर्चा है कि इसके पीछे जेब गरम करने का मामला है।

ऑटो में बैग काटकर आभूषण चोरी करने वाले तीन शातिर गिरफ्तार

लखनऊ, (संवाददाता)। नाका हिण्डोला थाना पुलिस और पश्चिमी जोन निगरानी दल की संयुक्त कार्रवाई में ऑटो में सवारियों का बैग काटकर आभूषण चोरी करने वाले तीन शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी की घटना से संबंधित पीली धातु के तार बरामद किए हैं तथा घटना में प्रयुक्त ऑटो को भी जब्त कर लिया है।पुलिस के अनुसार 31 मार्च 2026 को वादिनी नीतू तिवारी निवासी बड़ी जुगौली थाना गोमतीनगर ने लिखित सूचना दी थी कि वह ऑटो से जा रही थीं, तभी रास्ते में उनका बैग काटकर उसमें रखे सोने के आभूषण चोरी कर लिए गए। इस संबंध में नाका हिण्डोला थाना पर संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।घटना के खुलासे के लिए थाना पुलिस और पश्चिमी जोन के निगरानी दल द्वारा संयुक्त रूप से जांच की जा रही थी। इसी क्रम में 07 अप्रैल 2026 को रात्रि लगभग 9 बजकर 59 मिनट पर दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन के पास से तीन अभियुक्तोंकृ मोहम्मद इकरार उर्फ कल्लू निवासी जनपद बाराबंकी, अरमान निवासी गौस नगर मड़ियांव लखनऊ तथा अफजाल अहमद निवासी जनपद बिजनौरकृ को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके कब्जे से घटना से संबंधित पीली धातु के पांच ठोस तार, जिनका कुल वजन लगभग 11.380 ग्राम तथा अनुमानित मूल्य लगभग डेढ़ लाख रुपये है, बरामद किए।

मामूली विवाद में पत्नी ने पति को मौत के घाट उतार कर खुद दी जान,घटना में नवजात शिशु की भी हुई मौत

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या।जिले के रौनाही थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई हृदय विदारक घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। जो भी इस हृदय विदारक घटना को सुन रहा है उसके पैरों तारे जमीन खिसक जा रही है। और सभी यही कहते हुए दिखाई दे रहे थे आखिर ऐसा पति पत्नी की बीच में क्या विवाद हुआ साथ जीने मरने की कसम खाने वाली पत्नी हथौड़े से अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और 22 दिन के नवजात बच्चे को रोता भी लगता छोड़कर खुद ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी जो की एक बहुत ही बड़ा सवालिया प्रश्न बन रहा है।बताते चले कि पत्नी ने पति की हत्या करने के बाद खुद भी जान दे दी और 22 दिन के मासूम की मौत हो गई।अयोध्या जिले के थाना रौनाही क्षेत्र के करे। गांव में पति–पत्नी के बीच हुए विवाद ने एक खौफनाक रूप ले लिया जिसके परिणामस्वरूप तीन जानें चली गईं।एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने बताया कि महिला ने पति की हत्या करने के बाद उसके शव और नवजात शिशु को कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया था।इसके बाद वह घर से निकल गई और अयोध्या–लखनऊ रेल खंड पर देवराकोट के पास ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी। कमरे में बंद नवजात शिशु की भूख और प्यास के कारण दर्दनाक मौत हो गई।घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बलवंत चौधरी,सीओ आशीष निगम और रौनाही पुलिस टीम मौके पर पहुंची।पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।बताया कि घटना के समय मृतक पति के माता–पिता खेत में गेहूं काटने गए हुए थे।पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। इस हृदय विदारक घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि पति–पत्नी के बीच विवाद किस बात को लेकर हुआ था। आगे की कार्रवाई जारी है।

रुदौली कोतवाली मे तैनात उप निरीक्षक कृपा शंकर यादव का अमेठी स्थानांतरण होने पर हुई भावभीनी विदाई

(राजन तिवारी सिटी रिपोर्टर)

अयोध्या।रुदौली कोतवाली में तैनात उपनिरीक्षक कृपा शंकर यादव का गैर जनपद तबादला अमेठी हुआ है। उनके स्थानांतरण की सूचना मिलते ही कोतवाली परिसर में विदाई का माहौल भावुक हो गया।शुक्रवार को कोतवाली परिसर में उनके सम्मान में एक सादे लेकिन गरिमामय विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारी, सहकर्मी एवं पुलिस स्टाफ बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।सभी ने उन्हें माला पहनाकर और शुभकामनाएं देकर विदाई दी।इस मौके पर थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिस

कर्मियों ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि कृपा शंकर यादव ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ किया।उनके व्यवहार और कार्यशैली की सभी ने प्रशंसा की।अंत में कृपा शंकर यादव ने भी अपने सहयोगियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि रुदौली में बिताया गया समय उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा। उन्होंने सभी से मिले सहयोग के लिए धन्यवाद दिया।

डिप्टी जेलर व समीक्षा अधिकारी बनने पर हुआ स्वागत सम्मान

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या।क्षेत्र के कटैया भादी गांव निवासी डिप्टी जेलर बने अनुपम तिवारी और समीक्षा अधिकारी बनीं दिव्या सिंह का बुधवार को जोरदार स्वागत हुआ। भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय पाण्डेय ने अनुपम तिवारी और

दिव्या सिंह का फूल माला पहनकर मुंह मीठा करा कर भव्य स्वागत सम्मान किया।अनुपम तिवारी वर्ष 2024 की पीसीएस परीक्षा में पहले ही प्रयास में डिप्टी जेलर बने हैं। वहीं दिव्या सिंह भी पहले ही प्रयास में समीक्षा अधिकारी की परीक्षाएं पास की है। दोनों की सफलता से क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है।दोनों मेधावियों का सम्मान करने के लिए लोग उनके घरों तक पहुंच रहे हैं। भाजपा नेता विजय पाण्डेय ने कहा कि दोनों ने प्रशासनिक परीक्षा पास कर क्षेत्र का गौरव बढ़ाया है। ऐसे मेधावियों का सम्मान होना चाहिए, ये तैयारी कर रहे छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं।

बीमा क्लेम देने में आनाकानी, दो महीने में 221616 रुपये देने के आदेश

भदोही, (संवाददाता)। जिला उपभोक्ता आयोग ने कृषि कार्य के लिए पंजीकृत ट्रैक्टर का दुर्घटना होने पर बीमा राशि न देने की याचिका स्वीकार करते हुए इंश्योरेंस कंपनी को छह फीसदी ब्याज के साथ 221616 रुपये बीमा राशि अदा करने का आदेश दिया। कोर्ट ने पीड़ित को वाद व्यय के लिए पांच हजार रुपये देने का आदेश दिया। चेताया कि नियत तिथि में क्लेम की राशि न देने पर 12 फीसदी ब्याज से सभी धनराशि चुकानी होगी। जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि भदोही तहसील के हरियावं निवासी सुनील कुमार यादव ने कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर खरीदा। इसका उन्होंने एलआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा कराया। बीमा छह सितंबर, 2023 से पांच सितंबर, 2024 तक वैध था। तीन जनवरी 2024 को उनका ट्रैक्टर जोताई के दौरान पेड़ से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया। इसकी सूचना उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी को चार जनवरी 2024 को ही दे दी। आरोप है कि बीमा कंपनी के अधिकारी मौके पर जांच करने पहुंचे और गलत आख्या रिपोर्ट लगाई। इस पर बीमा कंपनी ने क्लेम देने से मना कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने 12 जुलाई 2024 को कंपनी के वाराणसी प्रबंधक और मुंबई में महाप्रबंधक के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। जिला उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन न्यायाधीश संजय कुमार डे और सदस्य न्यायाधीश दिप्ती श्रीवास्तव व न्यायाधीश विजय बहादुर सिंह की पीठ ने सुनवाई करते हुए याचिका स्वीकार करते हुए इंश्योरेंस कंपनी द्वारा उपभोक्ता की सेवा में कंपनी का दोषी पाया। कोर्ट ने कंपनी को दो महीने के भीतर बीमा क्लेम की धनराशि 221616 रुपये छह फीसदी ब्याज के साथ देने का आदेश दिया। चेताया कि दो महीने में क्लेम न देने पर पूरी धनराशि पर 12 फीसदी वार्षिक ब्याज के साथ देनी होगी।

मिशन शक्तिकार्यक्रम में नारी शक्तिको एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर किया सम्मानित सम्मान,स्वावलंबन पर दिया गया जोर

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। पुलिस लाइन सभागार में आयोजित मिशन शक्ति फेज– 5 द्वितीय चरण के अंतर्गत नारी शक्ति को नमन,सम्मान और स्वावलंबन विषय पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।कार्यक्रम में प्रेरणादायी महिलाओं,महिला समाजसेवियों एवं महिला पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. गौरव ग्रोवर तथा विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बलवंत चौधरी व एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी मौजूद रहे।इस दौरान महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर संज्ञान में लेकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी तथा अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।मुख्य अतिथि ने कहा कि महिलाएं थाने आने में संकोच न करें, इसके लिए महिला अधिकारियों द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही अपराध की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सतत निगरानी पर भी जोर दिया गया। उन्होंने सभी विभागों के समन्वय से कार्य करने की आवश्यकता बताई, जिससे महिलाओं को न्याय और सम्मान मिल सके।कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है और उनकी समस्याओं को सुनने के लिए महिला अधिकारी तत्पर हैं। वहीं एसपी ग्रामीण बलवंत सिंह चौधरी ने महिलाओं से समाज में सजग रहने और आत्मनिर्भर बनने का आह्वान किया।आईपीएस शुभम जैन ने भी अपने विचार व्यक्त किए।कार्यक्रम का संचालन क्षेत्राधिकारी नगर श्रेयस त्रिपाठी ने किया।इस अवसर पर यूपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों को भी सम्मानित किया गया।

पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने मृतक के परिजनों को सौपा एक लाख का चेक

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। पिछले दोनों शहर के एक निजी अस्पताल में चिकित्सा के लापरवाही के चलते जच्चा और बच्चा की मौत हो गई थी।प्रसव में लापरवाही से गई जच्चा बच्चा की मौत मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्व0 सोनी यादव के पति सुरेश के नाम 1 लाख चेक के रूप में सहायता राशि भेजी।पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने परिवार के परिजनों को चेक सौपा। प्रसव में लापरवाही से गई जच्चा बच्चा की जान मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्व0 सोनी यादव के पति सुरेश के नाम 1 लाख चेक के रूप में सहायता राशि भेजी।पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन व नि0 महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव ने परिवार को चेक देकर हर सम्भव मदद का भरोसा दिलाया।इस मौके पर पूर्व मंत्री ने कहा कि इस दुःखद घटना का संज्ञान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने लिया और हर सम्भव मदद का भरोसा दिलाया।1 लाख का चेक परिवार के नाम दिया,पूर्व मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमेशा पीड़ित दुखी व्यक्ति की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर मदद करते हैं।पूर्व मंत्री ने कहा कि लापरवाही ने जाने ले ली स्वास्थ्य मंत्री व उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक सिर्फ दिखावा करते हैं।बल्कि हकीकत में सरकारी अस्पतालों की मिलीभगत से ही प्राइवेट नर्सिंग होम चल रहे है इसी का जीता जागता सुबूत ये प्रकरण है। जिसमें जच्चा बच्चा दोनों की जाने चली गयी।अगर महिला अस्पताल एडमिट कर लेता तो शायद यह दुखद घटना न होती।नि0 महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव ने कहा कि ये बहुत ही दुःखद घटना थी जिसमें डाक्टर के ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है, मेरी प्रशासन से मांग है कि इस तरह के जितने भी प्राइवेट नर्सिंग होम होम है।उनकी जांच कर कार्यवाही करे जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाएँ रुक सके,महानगर अध्यक्ष ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभार प्रकट किया प्रवक्ता राकेश यादव एडवोकेट ने बताया।इस मौके पर महानगर अध्यक्ष श्याम कृष्ण श्रीवास्तव, महासचिव हामिद जाफर मीसम,अयोध्या विधानसभा अध्यक्ष रक्षा राम यादव, उपाध्यक्ष श्रीचंद यादव, प्रवक्ता राकेश यादव, श्रीमती लल्ली देवी,पूर्व चेयरमैन सुरेंद्र यादव,बृजेश सिंह चौहान,दान बहादुर सिंह, बृजेश यादव, करन यादव ,राजेश यादव,हरीश यादव, इत्यादि लोग मौजूद थे।

जलवानपुरा की सड़क होगी ऊंची,भ्रमण के दौरान महापौर ने किया जनता से वादा

(डॉ अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।इनगर की सरकार आपके द्वारश अभियान के तहत महापौर ने शुक्रवार को हनुमान कुंड वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ नगर आयुक्त जयेंद्र कुमार और पार्षद प्रतिनिधि अभय श्रीवास्तव भी थे।उन्होंने जलवानपुरा की सड़क को ऊंची कर करने का वादा किया।सुबह लगभग 9:00 बजे महापौर ने बिरला मंदिर के उत्तरी छोर की गली से भ्रमण की शुरुआत की। इस दौरान नगर निगम की टीम सफाई कर रही थी, लेकिन थोड़ी दूर चलने पर गोबर जमा देख कर उन्होंने नाराजगी जताई और हटाने का निर्देश दिया। महापौर के साथ चल रही नगर निगम की टीम ने श्रीराम भोजनालय के सामने रुक कर दुकानदारों से बात की और उन्हें कूड़ा–करकट कूड़ेदान में ही रखने की हिदायत दी। इस दौरान का तरीका भी बताया गया।थोड़ा आगे बढ़ने पर बिरला मंदिर के पिछले हिस्से में जलवानपुरा के लोगों ने जल भराव की समस्या से अवगत कराया। यहां रामनाथ पांडे ने बताया कि जलभराव से बरसात के दौरान घरों में रहना मुश्किल हो जाता है।पार्षद प्रतिनिधि ने क्षेत्रीय लोगों की समस्या को देखते हुए सड़क ऊंची करने की आवश्यकता जताई। पूछताछ के दौरान नगर आयुक्त को बताया गया कि अभी जल निगम सीवर लाइन डालने का कार्य कर रहा है। जल निगम के अधिकारियों ने वार्ता के दौरान दो माह में सीवर लाइन डालने का वादा किया। महापौर ने उन्हें दो माह के अंदर पाइप डालकर सड़क नगर निगम को हस्तगत कराने की हिदायत दी और लोगों से वादा किया कि इसके बाद सड़क को ऊंची करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।थोड़ा आगे बढ़ने पर सुबोध नारायण झा ने पानी न आने की शिकायत की। इस पर महापौर ने महाप्रबंधक जल निगम को पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान महापौर ने नालियों की सफाई मैनपॉवर से करने का निर्देश दिया।क्षेत्रीय नागरिक सिद्धार्थ ने महापौर नगर आयुक्त एवं पार्षद प्रतिनिधि का सम्मान भी किया। इस दौरान महापौर ने दंतधावन कुंड व स्थानीय लोगों की जरूरत के मुताबिक पर अंबेडकर पार्क के पास वाटर कूलर लगाने का वादा किया। उन्होंने विक्रम चौधरी के घर के सामने जलभराव को देखते हुए पंप लगाकर पानी हटाने का भरोसा दिया।यहां पंपिंग स्टेशन की भी आवश्यकता जताई गई।नगर आयुक्त ने प्रकाश व्यवस्था की भी जानकारी लोगों से ली।उन्होंने खराब लाइट को ठीक करने का निर्देश दिया।इस मौके पर अपर नगर आयुक्त डॉ. नागेंद्र नाथ, भारत भार्गव, महा प्रबंधक जलकर सौरव श्रीवास्तव, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी गजेंद्र कुमार, जोनल अधिकारी अशोक गुप्त, सहायक अभियंता जलकर जयकुमार, निर्माण खंड के सहायक अभियंता भारत वर्मा एवं राजपति यादव भी थे।

अपनी मांग को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री ने दिया प्रभारी डीआईओएस को ज्ञापन

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। शुक्रवार को मार्च माह का वेतन न मिलने के कारण माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री आलोक तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ो शिक्षकों ने शिक्षा भवन का घेराव किया।ज्ञातव्य हो कि विभागीय नियमानुसार 2 तारीख तक शिक्षक ध कर्मचारियों को वेतन मिल जाता है। और अभी तक मिलता रहा लेकिन मार्च माह का वेतन आज 10 अप्रैल तक शिक्षकों के खाते में नहीं भेजा गया। जिससे शिक्षकों के विभिन्न प्रकार की किस्त अवरुद्ध हुई बच्चों की फीस समय से नहीं जमा हो पा रही है मोबाइल का रिचार्ज नहीं हो पा रहा है एआई मे दक्षता नहीं हो पा रही है।छात्र–छात्राओं का पंजीकरण नहीं हो पा रहा है। वेतन न मिलने से पीड़ित शिक्षकों ने शिक्षा भवन का घेराव किया।कोई भी शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं रहा प्रभारी जिला विद्या निरीक्षक अवनीश कुमार पांडे को ज्ञापन दिया गया।वार्ता करने पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि वह विभागीय काम से शासन में

है।कल परसों अवकाश है सोमवार को ही वेतन भुगतान हेतु कोषागार भेजना संभव होगा संगठन निर्णय लिया है कि सोमवार को कार्यालय खुलते ही पुनः शिक्षक धशिक्षा अधिकारियों का घेराव किया जाएगा और कार्य बहिष्कार की घोषणा भी की जाएगी।घेराव में मुख्य रूप से महानगर अध्यक्ष अनूप पांडे, महानगर मंत्री सत्य प्रकाश सत्य, महानगर उपाध्यक्ष हसन अब्बास अतुल मिश्रा डॉ रंजीत वर्मा राकेश मौर्य आकाश गौर महेंद्र पाल कमलेंद्र संदीप ओझा राधेश्याम पांडे शिव प्रकाश कुलदीप अमित शर्मा राकेश मौर्या अरुण मिश्रा पंकज सिंह कमलेश पांडे ए मनोज वर्मा प्रदीप श्याम रंजन डॉ प्रतिभा पाठक देवेश पांडे अमित सिंह प्रमोद शुक्ला राजेश तिवारी भूपेंद्र देवचंद यादव राम इकबाल सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

महापौर के निवास स्थान तीन कलश मंदिर पर आयोजित सर्व समाजग्राही बना भगवान चित्रगुप्त जी की स्तुति आरती कार्यक्रम

(राजेश श्रीवास्तव ब्यूरो चीफ)

अयोध्या। गुरुवार की शाम अयोध्या स्थित तीन कलश मंदिर पर भगवान चित्रगुप्त जी की भव्य आरती का साक्षी बना।इस मौके पर महापौर गिरीश पति त्रिपाठी व उनकी पत्नी राज लक्ष्मी त्रिपाठी पत्नी ने भगवान चित्रगुप्त की आरती उतारी। तत्पश्चात सांसद अवधेश प्रसाद ने आशीर्वाद प्राप्त किया।बताते चलें भगवान चित्रगुप्त जी की आरती की शुरुआत 5 वर्ष पहले हुई थी अब यह कारवां सर्व समाज में ग्राही बन गया है।चित्रगुप्त भगवान की महिमा का वर्णन के लिए अब समाज के सभी वर्गों के लोग आगे आ रहे हैं। गुरुवार को हुई आरती में समाज सहित अन्य वर्गों के लोगों की बड़ी भागीदारी रही। कार्यक्रम के अंत में महापौर ने संगठन के सभी साथियों का अंग वस्त्र देकर सम्मान किया। प्रवक्ता जेपी श्रीवास्तव ने बताया कि भगवान की आरती का यह कारवां दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां समाज के लोग भागीदारी कर इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं तो वही अन्य समाज व वर्गों के लोग भगवान चित्रगुप्त की आरती का आयोजन करके अपनी भागीदारी बढ़ा रहे हैं।इस अवसर पर अरुण श्रीवास्तव अध्यक्ष, प्रतीक श्रीवास्तव महामंत्री, ज्ञानेश्वर भटनागर, आशीष श्रीवास्तव, देश दीपक जौहरी, विवेक श्रीवास्तव, दीपक श्रीवास्तव पलिया, डॉ पंकज श्रीवास्तव, अंशुमाली श्रीवास्तव, ऋषभ श्रीवास्तव, आशुतोष श्रीवास्तव, समेत बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग मौजूद रहे।

एसडीएम सोहावल के मुताबिक आवास लेने वाले आपात्रों पर शीघ्र होगी कार्यवाही,जांच समिति गठित

(डाक्टर अजय तिवारी जिला संवाददाता)

अयोध्या।नगर पंचायत भरतकुंड पर आवास में आपात्रो पर कार्यवाई होगी।आवासों की जांच उपजिलाधिकारी सविता देवी ने टीम गठित किया है।जमीन के कागजात निर्माण स्थल एवम पात्रता प्रमुख होंगे।बिंदु राजस्व के संक्षम अधिकारी एवम डूडा एवम नगर पंचायत के ई ओ जांच कमेटी में शामिल है।एक बार सोहावल तहसील उपजिलाधिकारी सविता देवी ने कड़ा रुख अपनाते हुए नगर पंचायत भदरसा भरतकुंड पर जांच शुरु कर दी है। जिसमे तहसील के दो उच्च अधिकारी व लेखपाल, कानूनगो, नगर पंचायत भरतकुंड के ईओ और डूडा के एक कर्मचारी जांच में होंगे।जिसमे मुख्य रूप से 3 बिंदु पर जांच होगी।पात्रता निर्माण स्थल और जमीन के कागजात मुख्य रूप से होंगे।वही उपजिलाधिकारी सोहावल सविता देवी ने साफ कह दिया है कि जो पात्र है उन्हें कोई समस्या नही जो अपात्र है और सरकारी जमीन कब्जा करने का प्रयास कर रहे है या जिनके पास पहले से मकान है योजना का गलत तरीके से लाभ लेने की कोशिश कर रहे है उनसे रिकवरी के साथ कार्यवाही भी की जाएगी।वही कुछ और मकानों की पात्रता को लेकर जिन्हें अभी भुगतान नही हुआ है उनकी जांच कर उनसे सपथ पत्र के साथ आवास दिया जाएगा यदि कुछ छिपाकर सपथ पत्र दिया जाता है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।सविता देवी ने बताया कि आवास की व्यवस्था गरीब असहाय और जिनके पास मकान नही है उनके लिए है यदि कोई उसका दुरुपयोग करेगा तो उसपर कार्यवाही की जायेगी।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।